

बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना

1332. श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार की गणना पिछड़े राज्यों में की जाती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बिहार के मुख्य मंत्री ने राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना पेश की है, यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इम बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीर्षन वारिया) . (क) जी हाँ ।

(ख) बिहार राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये मुख्य मंत्री द्वारा भेजी गई स्कीम की कोई जानकारी योजना आयोग को नहीं है । किंतु श्री पिछड़ेपन के मामले पर उन्होंने चर्चा की और अपनी स्कीम भेजने को कहा है ।

(ग) प्रभन नहीं उठता ।

बिहार स्वतंत्रता सेनानी सहायता समिति द्वारा दिया गया सुझाव

1333. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में बिहार स्वतंत्रता सेनानी सहायता समिति की ओर से कोई प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल से कोई सुझाव भी दिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके मुख्य बातें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार को क्या क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपसंचारी (श्री एफ० एच० शौहसिन) . (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). बातचीत का सम्बन्ध पश्चात के मामला के शीघ्र निपटाने को सरल बनाने की प्रक्रिया से था । स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी करने के लिए हर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

प्राकृतिक संदर्भ के विकास के लिए बोर्ड के गठन करने का प्रस्ताव

1334 श्री रामावतार शास्त्री : क्या विकास और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी के अध्यक्ष श्री दी० शार्ट० फैसालार ने गत दिसम्बर महिने में हैदरगाबाद में आयोजित राष्ट्रीय श्रीगोलिक अनुसंधान रत्न जयंती का उद्घाटन करने हुए प्राकृतिक सम्पदा विकास एवं वृद्धि के लिये एक समिति या बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीगोलिक विकास तथा विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुदूरमण्डल) :

(क) जी हाँ ।

(ख) देश के प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्ध का विकास कई मंत्रालयों के क्षेत्राधीन है एवं ऐसे मंडल (बोर्ड) की स्थापना के विचार से पहले अन्तर-मंत्रालय परामर्श तथा विकास विमर्श की प्रचार आवश्यकता होती है ; यह विषय विचाराधीन है ।